

13

31/8/12

खण्ड - 03

संख्या - 04,06

नवम्

बिहार विधान—सभा वादवृत्त

भाग -2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित



सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक 08 नवम्बर, 1985 ई०

बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर, 1985 ई०

में विचार होगा ।

सभापति (श्री नरसिंह बैठा) शांति, शांति, सदन की मंशा को देखते हुए मैं इसको पेंडिंग करता हूँ ।

मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा प्रदान करना :

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, “यह सभा राज्य सरकार से अधिस्ताव करती है कि वह मुंगेर, खगड़िया एवं बेगूसराय को मिलाकर मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा प्रदान करे ।”

सभापति महोदय, मुंगेर एक बहुत ही पुराना जिला रहा है । 1832 ई० में मुगल जमाने के समय में मुंगेर जिला का निर्माण हुआ था । इसका एक अंग बेगूसराय जो मुंगेर जिला में ही पहले था को 2.10.72 को मुंगेर जिला से अलग कर बेगूसराय को जिला का दर्जा दिया गया । खगड़िया भी जो मुंगेर का ही एक अंग था को 10.5.81 को अलग किया गया । अभी मुंगेर जिला की जनसंख्या जो है वह 33 लाख 14 हजार 806 और बेगूसराय की जनसंख्या 14 लाख 56 हजार 512 है । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि खगड़िया और बेगूसराय जो मुंगेर जिला की एक अंग था, आज वह अलग हो गया तो, ये जब तीनों इसी का अंग रहा है और अलग-अलग हो गया तो, सरकार को तीनों को मिलाकर मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा देना चाहिए ।

सभापति महोदय, जिला बनने से जो विकास की गति है वह तीव्र होता है और प्रशासन की दृष्टिकोण से इसके

एडमिनिस्ट्रेट्रिव सुधार की दृष्टिकोण से, अच्छा प्रशासन की दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो गया है कि मुंगेर को कमीशनरी बनाया जाए ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी कमीशनरी का जो दर्जा दिया जाता है, इसमें खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर का जो क्षेत्रफल है वह उसको संतुष्ट करता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुंगेर जिला पर्षद ने सर्वसम्मति से रेज्यूलेशन लेकर एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा कि मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा दिया जाना चाहिए । मुंगेर जिला पर्षद में सभी दल के लोग हैं और माननीय सदस्यों की भावना है, जनता की भावना है, उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि सरकार उस रेज्यूलुखन की ओर तो ध्यान दे । जब श्री चन्द्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके पास पत्र लिखा था और उन्होंने कार्मिक विभाग को कंसीडरेशन के लिए भेजा । राज्य के विभिन्न जिलों का पुनर्गठन आप कर रहे हैं, ऐसे नाजुक समय में मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा देने का जो समय है वह परिपक्व समय आ गया है और सरकार को इस पर विचार कर आज विधान सभा में डिक्लेयर करना चाहिए । मुंगेर जो डॉ० श्रीकृष्ण सिंह का जिला रहा है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस चीज को मद्दे नजर रख कर तो कमीशनरी का दर्जा देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ।

इन्हीं शब्दों को रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह मुंगेर को विशेष वर्जा दिया जाए ।

श्री हरखू झा: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संकल्प की अंतिम पंक्ति में शब्द “जिसका मुख्यालय मुंगेर में हो” जोड़े जायें ।

सभापति महोदय, मुंगेर एक ऐतिहासिक जिला रहा है, वहाँ दानवीर कर्ण रहा करते थे, जो प्रति दिन सवा मन सोना दिया करते थे, यह मुगल-शासन का केन्द्र रहा है, अंग्रेज के जमाने से यह जिला बहुत ही पुराना रहा है । राजनीतिक दृष्टि कोण से देखा जाए तो मुंगेर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि एक तरफ गंगा अपनी विनाश की लीला से सारे गांवों और शहर को जर्जर बना दिया है दूसरी तरफ इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं जिससे वहाँ प्रगति नहीं हो पा रही है । प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर क्राईम बहुत बढ़ गए हैं, चोरी, डकैती बढ़ गई है, इससे मुंगेर को कमीशनरी का दर्जा देना बहुत ही आवश्यक हो गया है; मैंने संशोधन किया है कि कमीशनरी का मुख्यालय मुंगेर में हो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जगह तो कमीशनरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन मुख्यालय के बारे में स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण बाद में ऑफीसर्स लोग धांधली करते हैं, लोग कहते हैं कि फला जगह हो, दूसरे कहते हैं कि फलां जगह हो इस तरह की दुविधा न हो इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि कमीशनरी जो बने उसका मुख्यालय मुंगेर में ही हो

ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा न हो, मुंगेर से यातायात का सम्पर्क डायरेक्ट बना हुआ है, इसके अतिरिक्त मुंगेर का टूरिस्ट सेन्टर भी है। मुंगेर में मीरकासिम का किला है। वहाँ बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, बड़े नेता हुए हैं और भी हैं इसलिए बड़े बड़े लीडर के रहते हुए मुंगेर मुख्यालय नहीं हो तो यह अन्याय है। इसलिए खण्डिया, बेगूसराय और मुंगेर तीनों को मिला करके कमिशनरी बने और इसका मुख्यालय मुंगेर हो।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिये करता हूँ कि मैं मुंगेर जिला से आता हूँ ऐसा नहीं है, समर्थन इसलिये करता हूँ कि मुंगेर कमिशनरी नहीं बनने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। सभापति महोदय, जब बिहार, बंगाल एक था तो उस समय पटना, भागलपुर और राँची यह तीन कमिशनरी थीं। सन् 1907 में तिरहुत कमिशनरी का निर्माण हुआ। आजादी के बाद डॉ० जगन्नाथ बिहार के मुख्यमंत्री ने यह महसूस किया कि इस राज्य में कमिशनरी और जिला का निर्माण होना चाहिये। चौंकि विकास का काम बढ़ता गया, सामाजिक वातावरण इस तरह को होता गया जैसा कि अभी माननीय, सदस्य श्री हरखू झा ने कहा है कि अपराध की गतिविधि बढ़ गयी है। सन् 1972 तक कोई भी कमिशनरी का निर्माण नहीं हुआ था। इसके लिये तीन आदमी का कमिशन बना, जिसमें बक्शी, बी०पी० पांडेय और रणधीर प्रसाद जो उनलोगों ने सुझाव दिया कि

कमिशनरी का निर्माण होना चाहिए, जिला का निर्माण होना चाहिए और सब-डीविजन का निर्माण होना चाहिए लेकिन वैसा नहीं किया गया। सन् 1972 में कोशी और दरभंगा का निर्माण हुआ। उत्तर छोटानागपुर का निर्माण हुआ। डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने 1980 में सारण, मगध और संथाल-परगना कमिशनरी का निर्माण किया। सभापति महोदय, मुंगेर जिला में डॉ० श्री कृष्ण सिंह, नन्दकुमार सिंह, कार्यानन्द शर्मा आदि जैसे सामाजिक नेता और कार्यकर्ता पैदा हुए। जितने भी पुराने सब-डीविजन माने जाते हैं उसमें मुंगेर जिला के सब-डीविजन आते हैं फिर भी इसे कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया गया और मुंगेर के साथ अन्याय किया गया। जब चन्द्रशेखर बाबू इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए यह अवसर आया कि मुंगेर का सब-डीविजन जमुई जिला बने लेकिन वहाँ के लोगों की यह तमन्ना दिल-ही-दिल में रह गयी और जमुई को जिला का दर्जा नहीं मिल सका। और उस जिला में रहने वाले लोगों की ऐसी तमन्ना थी कि मुंगेर कमिशनरी बने। चन्द्रशेखर बाबू मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा देना चाहते थे, उन्होंने इसके लिये कमिटी का निर्माण किया लेकिन मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा अभीतक नहीं मिल सका। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के आग्रह करना चाहता हूँ कि जो क्राइटरिया अन्य कमिशनरियों के बनाने में रखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय क्योंकि अन्य कमिशनरियों से कहीं ज्यादा बढ़-चढ़ कर मुंगेर हक रखता है। इसलिये माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद

वर्मा, जो मुंगेर से आते हैं, ने जैसा प्रस्ताव दिया है, उसपर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुंगेर के साथ बहुत तरह का अन्याय हुआ है। बेगूसराय को मुंगेर से काटकर दरभंगा कमिशनरी में मिला दिया गया। मुंगेर को आपने सिर्फ कमिशनरी का दर्जा ही नहीं दिया बल्कि अपने उसके सारे अस्तित्व को निकाल दिया। अपने बेगूसराय को मुंगेर से काटकर दरभंगा कमिशनरी में क्यों जोड़ दिया? आपने बेगूसराय को दरभंगा कमिशनरी में इसलिये जोड़ दिया कि दरभंगा को कमिशनरी बनाने के लिये उसकी उपयोगिता, उसका जस्टिफिकेशन चाहते थे। मेरा सरकार से आग्रह है कि बेगूसराय, खण्डिया और जमुई को मिलाकर मुंगेर को कमिशनरी को दर्जा दे और उसका मुख्यालय मुंगेर में बनाया जाए। इधर हाल ही में अपने शेखपुरा को सबडिवीजन बनाया है। लखीसराय भविष्य में एक दिन जिला के दर्जा में आएगा और इस तरह तीन-चार जिला मुंगेर में आ जाएगा। इस तरह तीन-चार जिला मिलाकर मुंगेर को आप कमिशनरी का दर्जा दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो प्रस्ताव दिया है, उसपर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें और फैसला लें।

श्री भोला सिंह : सभापति महोदय, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जी ने संकल्प

रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेगूसराय और खगड़िया तथा मुंगेर को मिलाकर एक कमिशनरी बनाया जाय, मैं उनके इस प्रस्ताव के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूँ। मैं इस प्रस्ताव का इसलिए समर्थन नहीं करता हूँ कि मैं बेगूसराय जिले का रहनेवाला हूँ। इसका समर्थन मैं इसलिए करता हूँ कि मुंगेर मात्र जिला ही नहीं है, मुंगेर कमिशनरी भी होगा तो वह मात्र कमिशनरी ही नहीं होगा, बल्कि मुंगेर का वह महत्व है, वहां ऐसे महापुरुष हुए हैं, वहां की आबादी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में बड़े-बड़े प्रतिभावादी युवक निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया और मूंगेर राष्ट्रीय संस्कार का प्रतिबिम्ब है और उस शरीर के हम अंग है। उस इतिहास के साथ, उसकी संकृति के साथ, उसकी सामाजिकता के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा भी आग्रह है कि मूंगेर जिला को कमिशनरी बना दें।

कमिशनरी बनाने के लिए हमेशा राजनैतिक निर्णय हुआ करता है। दरभंगा कमिशनरी हुआ, इसका भी राजनैतिक निर्णय हुआ, दूसरे कमिशनरी भी हुए, उस संबंध में भी राजनैतिक निर्णय हुए लेकिन मुंगेर का बेटा जब सर्वोच्च ऊँचाई पर बैठा तो उन्होंने हमेशा इसका ख्याल किया कि कोई व्यक्ति उसकी तरफ निगाह नहीं उठाए कि वह उस जिले का था इसलिए उसकी कमिशनरी बना दिया। इस ख्याल से भी हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उनके ऊपर आजतक किसी ने क्षेत्रीयता का आरोप नहीं लगाया, कभी किसी ने इसके लिए उनपर ऊँगली नहीं उठायी। उन्होंने हमेशा बिहार

के संदर्भ में अपने को सोचा, समझा इसलिए आज जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ। एक इतिहास के साथ रहने के कारण, स्वतंत्रता संग्राम में साथ रहने के कारण, भौगोलिक स्थिति में रहने के कारण मुंगेर के साथ हमारा जो संबंध है जो हमारी संवेदनशीलता है उसके साथ जुड़ता हुआ होने के कारण मैं आग्रह करूँगा कि सरकार इस पर विचार करे और वह मुंगेर को कमिशनरी बनाए ताकि उस कमिशनरी के साथ बेगुसराय और खगड़िया का संबंध बना रहे। हम दरभंगा कमिशनरी में रहने के कारण बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। दरभंगा के साथ न हमारी संस्कृति मिलती है और न संस्कार मिलता है। दरभंगा के लोग हमको देखते हुए पानी-पानी हो जाया करते हैं, हमारी उपस्थिति उनको सह्य नहीं होती है और वहाँ हमारा शोषण होता है, हमारे प्रतिभावान वहाँ पिछड़ जाते हैं, वहाँ हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार होता है। हम अपने को वहाँ अभीतक ऐडजस्ट नहीं कर पाए हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, मुंगेर का शरीर काटकर दरभंगा के साथ प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ दिया गया है, यह हमारे साथ अन्याय है। हम मुंगेर के अंग हैं, मुंगेर के शरीर हैं, मुंगेर हमारी आत्मा है। मुंगेर मीरकासिम के जमाने में उसके राज्य का मुख्यालय रहा है। मुंगेर में राजा कर्ण जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति का स्थान रहा है। मुंगेर वह स्थान है जहाँ आजादी की लड़ाई के व्यूह की रचना की गयी थी। इस ऐतिहासिक मुंगेर से हमारे शरीर को काटकर अलग किया गया

है, हम चाहते हैं कि अभी भी हमारा शरीर उससे जुड़ जाय और मुंगेर को कमिशनरी बनाया जाय ।

हमारा आग्रह है, माननीय मंत्री जवाब देते समय अपना विचार प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम बातों का वे ख्याल करेंगे । इसी आशा के साथ, इन्हीं शब्दों में से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री नीतिश कुमार : सभापति महोदय, मैं श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । मुंगेर जिला के एक हिस्से को अर्थात् बेगूसराय को दरभंगा कमिशनरी में जोड़ दिया गया है, यह उचित नहीं है । श्री भोला सिंह ने ठीक ही कहा है कि बेगूसराय जिला की संस्कृति का दरभंगा से कोई मेल नहीं खाता है । मिथिला की संस्कृति मुलायम है किन्तु मुंगेर जिला की संस्कृति कड़ी है, कठोर है । इसलिये इससे उसकी संस्कृति का कोई मेल नहीं खाता है । दूसरी बात है कि खगड़िया की भी संस्कृति मिथिला से कोई मेल नहीं खाती है । मुंगेर की भाषा कड़ी है । इसी तरह से बेगूसराय और खगड़िया की भाषा भी कड़ी है । पुराने मुंगेर जिला में ही बेगूसराय और खगड़िया था । इसलिए इसे काटकर किसी को दरभंगा और किसी को कोशी में नहीं मिलाया जाय । अतः मुंगेर जिला, बेगूसराय जिला और खगड़िया को इन तीनों को मिलाकर मुंगेर कमिशनरी बनायी जाय जैसा कि तीन जिला को मिलाकर मगध कमिशनरी बनी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ ।

श्री ध्रुव भगत : सभापति महोदय, मुंगेर का इतिहास त्याग और तपस्या

का रहा है। स्वतंत्रता के संग्राम में मुंगेर जिला सभी जिलाओं से अग्रणी था। आजादी के पहले मुंगेर जिला का जो भौगोलिक रचना था, उसकी संस्कृति की जो रचना थी और आजादी के पहले मुंगेर का जो विकास हुआ था, आजादी के बाद नहीं हुआ। आजादी के बाद इसको कुछ नहीं मिला। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद इसके भौगोलिक रचना को तोड़ा गया है। इसकी संस्कृति की रचनाओं को तोड़ा गया है और इसकों कुछ नहीं मिला है। जबकि सभी जिलाओं में नये-नये उद्योग खोले गये हैं, जो थाना था उसको कमिशनरी का दर्जा दिया गया है। उसको काटने से मुंगेर काफी कमजोर हो जाएगा। मुंगेर की आत्मा और उसकी धरती शुरू से हीं अकेला रहा है। मुंगेर के लोग बिहार में ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान में अगर किसी कोने में चले जायेंगे और कोई पूछता है कि कहाँ मकान है, अगर मुंगेर जिला कहता है तो लोग उसे घूर-घूर कर देखने लगते हैं। मुंगेर ने बिहार को दो-दो योग्य मुख्यमंत्री दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को सुख-दुख में साथ दिया और बिहार का पिकास किया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचे तो इस नतीजे पर आसानी से पहुँच जायेंगे कि जिस तरह से सहरसा और संथालपरगना को आपने कमिशनरी का दर्जा दिया है, उसी तरह से मुंगेर को भी दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि बड़े ही उचित समय

पर श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है। इसलिए मैं सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ निवेदन करना चाहता हूँ कि मुंगेर को तुरन्त कमिशनरी बनाया जाय और इसी में बेगूसराय और खगड़िया को रखा जाय, क्योंकि ये दोनों जगहें इसका अपना अंग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूँ।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने यह जो गैर-सरकारी संकल्प सदन में लाया है, उससे हमारी सहमति है। मैं चाहता हूँ कि मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया को मिलाकर जो इसके भूतकाल के अंग रहे हैं मिलाकर मुंगेर को कमिशनरी बनायी जाय। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी राज्य सरकार ने जिला, प्रमंडल आदि का पुनर्गठन किया है, प्रशासनिक सुधार आयोग की राय से किया है। 1975 में स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री केदार पांडेय ने नये जिला का संगठन किया था, वह भी आयोग की अनुशंसा पर ही। इसका आधार वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के प्रशासनिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए ही पुनर्गठन किया गया है। जिला न्दर उस समय मगध प्रमंडल बनाया गया था और उसके पीछे कई उदाहरण हैं। राजो बाबू और भोला बाबू ने जो कहा है वह ठीक ही है। वहाँ की जनसंख्या, आबादी, ऐतिहासिक, अपराधिक संख्या आदि को देखते हुए जिला या कमिशनरी का पुनर्गठन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंगेर जिला में 22 प्रखंड है, खगड़िया में 6 और बेगूसराय में 11 प्रमंडल हैं,

कुल मिलाकर 39 प्रखंड हैं। जिस तरह से गया जिला में 42 प्रखंड है और तीन जिला गया, नवादा और औरंगाबाद का पूर्णगठन हुआ 1972 में और 18 अप्रैल 1981 में डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने तीनों जिला का कमिशनरी मण्डल बनाया। मैं कहना चाहता हूँ कि गया के जैसा ही मुंगेर जिला भी है। अतः मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय। सारी चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए चाहे वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही क्यों न हो, मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय।

यह मैंने वहाँ की जनसंख्या और प्रखंडों की संख्या के आधार पर कहा। मुंगेर के बारे में माननीय सदस्य, श्री ध्रुव भगत ने जो इशारा किया और सदन को जानकारी दी कि वहाँ सिगरेट की फैक्ट्री है, रेलवे शेड है तथा ओर्डिनेन्स फैक्ट्री है। जमालपुर को भी देखा जाय तो वह भी किसी जिला से कम नहीं है। वहाँ भी इंडस्ट्रीयल कम्प्लेक्स है जिस प्रकार जमशेदपुर है, वह भी सिंहभूम जिला में पड़ता है लेकिन वह जिला नहीं बना है। जमशेदपुर की तरह ही जमालपुर भी है, लखीसराय भी है। इन स्थानों में काफी इंडस्ट्रीयल कम्प्लेक्स है। यह सही है कि बिहार का एकमात्र सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे कि मुंगेर को यथाशीघ्र कमिशनरी का दर्जा दिया जाय।

श्रीमती शंकुतला सिन्हा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र

प्रसाद वर्मा के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूँ और मैं इसलिए इस पर बोल रही हूँ कि मैं बेगूसराय जिला का हूँ और मुंगेर जिला में मैं पहले थी। इसलिए बेगूसराय को मुंगेर के अन्दर ला कर मुंगेर को कमिशनरी का मुख्यालय बनाना चाहती हूँ। जिन माननीय सदस्यों ने श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन किया है, उसीका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूँ, उनकी बातों को दुहराना नहीं चाहती हूँ। मुंगेर के महत्व को कहने के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी। इतना मैं जरूर कहूँगी कि मुंगेर की भौगोलिक स्थिति बहुत उमदा है, वहाँ देश के दूर-दूर से स्वास्थ्य लाभ के लिए आया करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से मुंगेर के अन्दर खगड़िया और बेगूसराय का रहना ठीक होगा और बेगूसराय को दरभंगा के साथ रहने से वहाँ के लोगों को काफी कठिनाई है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि मुंगेर में खगड़िया और बेगूसराय जिला को लेकर ही कमिशनरी बनाया जाय। इसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करती हूँ।

श्री अलख शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुंगेर का महत्व महाभारत काल में रहा है और इस समय भी रहा है। मुंगेर विभिन्न राजनैतिक कारणों से भी अपने आप में अच्छा रहा है और आज स्थिति यह है कि मुंगेर के नाम पर विभिन्न जिलों को बनाया गया। मुंगेर अपने समर्थ शक्तियों को ढोया चला जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि मुंगेर के समुचित

विकास के लिए उसको कमिशनरी का दर्जा दिया जाय। मुंगेर की जनता कर रही है कि :

कदम-कदम पर के छाले पड़े हुए हैं,
न जाने किस मुसीबत में मुंगेरवाले पड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहूँगा कि प्रजातांत्रिक ढंग से मुंगेर का प्रश्न हल किया जाय। हम और आप प्रजातांत्रिक पद्धति के अन्दर जी रहे हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति के अन्दर इंसान की भावनाओं के आयाम देने का कुछ अवसर नहीं मिल रहा है। आज मुंगेर में विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रीज हैं। यह जानकर बहुत दुख होगा कि मुंगेर में तमाम इंडस्ट्रीज का निर्माण भारत की आजादी के पूर्व ही हुआ। हमारे श्री बाबू ने केवल मूंगेर ही को नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक आयाम दिया और उन्होंने मुंगेर में रहते हुए बिहार को एक अजीब शक्ति दी और आपसे अनुरोध है कि श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के प्रस्ताव के समर्थन में मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय।

श्री मुंशीलाल राय : सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जिसको जैसी संस्कृति रही है उसको उसी हिसाव से कमिशनरी और जिला बनाया गया है। गोपालगंज और सिवान को एक जगह मिला दिया गया है, भौगोलिक दृष्टि और भाषा के हिसाव से छपरा को उसका कमिशनरी बनाया गया है। हसी तरह बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया तीनों की संस्कृति एक है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके

माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें वित्तीय भार कम पड़ेगा क्योंकि मुंगेर अपने आप में एक जिला है। एक बात और कहना चाहता हूँ और आप जानते होंगे कि सहरसा मुंगेर जिला में था और सहरसा जिला अब कमिशनरी बन गया है लेकिन मुंगेर जहाँ का तहाँ रह गया है। पता नहीं इसका क्या कारण है। कारण तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इतना कहूँगा कि राजनैतिक घुस इसका कारण हो सकता है। कोई मंत्री बन जाते हैं तो वे जिला बना लेते हैं। इसलिए यह राजनैतिक घुस हुआ। वैशाली जिला में कोई सबडिविजन नहीं है। वहाँ भी कई जगह ऐसे हैं जिसको सबडिविजन बनाया जाना चाहिए लेकिन नहीं बनता है। राजनैतिक घुस देनेवाले वहाँ कोई नहीं है। आज मुंगेर के नाम पर लूटते रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुंगेर का कोई आदमी मंत्री नहीं बना। सभापति महोदय, वहाँ के जो बड़े आदमी रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, श्री बाबू के बाद जो लोग मंत्री बनते गये, उन्होंने कुछ कर लिया। हम तो श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस्तरह का प्रस्ताव दिया।

अभी श्री महावीर चौधरी जो मुंगेर के हैं वोट देंगे कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगले चुनाव में वहाँ की जनता इन्हें निकाल देगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सभी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय।

श्री हिन्द केशरी यादव : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पालित जी का ससुराल मुंगेर में है इसलिए उनको बोलने के लिए समय दिया गया लेकिन मेरा ससुराल राजो बाबू के यहाँ है और मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया।

सभापति (श्री नरसिंह बैठा) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बुधन यादव : सभापति महोदय, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो गैर-सरकारी संकल्प लाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और मुंगेर जिला को कमिशनरी बनाने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं कि बिहार का जिसने 17 वर्षों तक नेतृत्व किया, महामहिम श्री श्रीकृष्ण सिंह को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी मुंगेर को कमिशनरी नहीं बनाया गया। इसलिए कि वे बेगूसराय और खगड़िया को बिल्कुल भाई की तरह समझते रहे लेकिन बाद में इसका बटवारा कर दिया गया और जिस श्री बाबू का सपना था कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया का एक ही भौगोलिक दृष्टि से समझते थे, सिद्धांतिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से और इसे एक ही बना रहना चाहते थे और मैं समझता हूँ कि इसी ख्याल से उस समय के मुख्यमंत्री श्री बाबू ने थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण बरौनी में किया जिसे मुंगेर में भी बनाया जा सकता था। आप सोच सकते थे। जब चन्द्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री हुए और वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के साथ जब वे मुंगेर के दौरे पर गये थे और मुंगेर

मैं श्री राजीव गांधी ने स्वयं यह तय किया था कि मुंगेर को 'कमिशनरी बनाया' जाएगा और हर्षध्वनि के बीच इसका एनाऊन्समेन्ट हुआ था। लेकिन आज तक मुंगेर को कमिशनरी नहीं बनाया जा सका है। इसके लिए हमें बहुत दुख है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जिस मुंगेर नगरी में लोगों ने आजादी की लड़ाई के दिनों में हर कोने-कोने में लोग मरने के लिए तैयार थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह : सभी लोग मुंगेर को कमिशनरी बनाने के लिए कह रहे हैं लेकिन कुछ कौन जिला इसमें जाएगा यह नहीं कह रहे हैं।

श्री बुद्धधन यादव : सभापति महोदय, जिस मुंगेर में बहुत कुछ पहले से था लेकिन सहरसा जो एक थाना के लायक भी नहीं था लेकिन उसे वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सहरसा को कमिशनरी में बदल दिया और जो जिला के लायक भी नहीं था वहाँ पर आज प्रमंडल स्थापित है और जबकि मुंगेर में जो इतना बड़ा क्षेत्र है, और इसका तीन-तीन, चार-चार जिला बना दिया गया लेकिन आज तक मुंगेर की उपेक्षा की जा रही है और मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, जिस मुंगेर में औद्योगिक प्रतिष्ठान पहले से स्थापित थे, चाहे सिगरेट फैक्ट्री हो, चाहे बंदुक फैक्ट्री हो ये सभी आजादी के पहले के हैं लेकिन आजादी के बाद वहाँ पर कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा

दिया जाए। साथ-ही-साथ मैं यह भी कह रेना चाहता हूँ कि मुंगेर नगरी वह नगरी है जहाँ पुराने जमाने की चण्डी स्थान है जहाँ पर दान देने वाले थकते नहीं थे चाहे लेने वाला कितना ही क्यों न हो और उसी मुंगेर नगरी में कर्णगढ़ है जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जायेंगे वहाँ पर सोना का वितरण होता था। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूँगा कि मुंगेर को अविलम्ब कमिशनरी का दर्जा दिया जाए।

श्री योगेश्वर झा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो गैर सरकारी संकल्प उपस्थापित किया है जिसमें मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय की बात है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। राजो बाबू खुश होंगे और भोला बाबू भी खुश होंगे कि मुंगेर कमिशनरी बने और हमलोग भी चाहते हैं कि बेगूसराय को दरभंगा कमिशनरी से अलग करके मुंगेर कमिशनरी बनाकर उसमें मिला दिया जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुंगेर अभीतक कमिशनरी इसलिए नहीं बना, वहाँ के श्री बाबू जैसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री बने, उसके बाद चन्द्रशेखर बाबू मुख्य मंत्री बने लेकिन अभी तक मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया गया। भोला बाबू ने कहा कि हमारे जो सपूत हैं दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं और आज तक का जो इतिहास है कि जो बहादुर होता है, जो सपूत होता है, जो बड़ा आदमी होता है वह जो सच्ची बात है कहता है लेकिन मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि श्री बाबू वहाँ के थे, चन्द्रशेखर बाबू वहाँ के थे और वे लोग इसे बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि संस्कृत में एक

कहावत है “यौवन, धन सम्पति प्रभुत्व अविवेकता एकैकम् अनर्थयः किमान् चतुर्प्रयम्” । और इसे गंभीरता को समझते थे वे इसे जानते थे कि बेगूसराय, खगड़िया, लक्खीसराय और मुंगेर चारों को एक जगह नहीं रहने दिया जाय और चारों एक जगह मिल गया तो क्या होगा ? इसीलिए श्री बाबू, चन्द्रशेखर बाबू या अन्य लोगों ने इसे एक नहीं होने दिया, एक जगह क्यों नहीं किया ? हमलोग दरभंगाबासी और दरभंगा कमिशनरी के लोग शांतिप्रिय लोग हैं । जैसे एक साधु के गिरोह में एक डकैत शामिल हो गया और साधु बन गया, रात होती थी तो डकैत सोचता था कि कैसे डकैती करें और साधु को होता था कि कैसे यह अलग हो जाय, इसलिए हमलोगों की हार्दिक इच्छा है कि जो कल होना है वह आज ही हो जाय और मुंगेर को आजही कमिशनरी बना दिया जाय ।

श्री रामलाल सिंह : सभापति महोदय, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो संकल्प पेश किया है कि मुंगेर को कमिशनरी बनाया जाय उसका मैं समर्थन करता हूँ । इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने जो प्रशासनिक कमिटी बनायी थी जिलों और कमिशनरी के पुनर्गठन के बारे में उसकी ओर से आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ तो प्रशासनिक कमिटी ने बिहार में और नौ जिले बनाने के बारे में रिपोर्ट दी है और उसमें भभुआ को जिला बनाने की रिपोर्ट दी है । मैं कहना चाहता हूँ कि भभुआ, सासाराम और आरा की एक संस्कृति है, एक भाषा है । इसलिए आरा को रोहतास कमिशनरी बनाकर वहाँ कमिशनरी बनाया जाय और भभुआ

को जिला बनाया जाय। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भभुआ को जिला बनाना बहुत ही आवश्यक होगा।

श्री राधाकृष्ण किशोर : माननीय श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो गैर-सरकारी संकल्प सदन में पेश किया है कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय तो मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। सभापति जी, मेरा वचपन मुंगेर में गुजरा है ओर मेरी प्रारम्भिक शिक्षा भी मुंगेर में हुई है। मैं मुंगेर को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुंगेर ने बड़े-बड़े वीर-बांकुरे इस राज्य को दिए हैं। मुंगेर को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रमंडल बनाना अनिवार्य है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुंगेर जिला अपराधिक मामले में भी बहुत पीड़ित रहा है। इसलिए मुंगेर को प्रमंडल बनाया जाय। साथ ही श्री जयकुमार पालित ने जैसाकि कहा कि उनका ससुराल मुंगेर ने पड़ता है इसलिए उसको प्रमंडल बनाया जाय तो इस हिसाब से मुंगेर को प्रमंडल बनाया जाता है तो बिहार के सभी जिले को प्रमंडल बनाना होगा क्योंकि सभी विधायकों को किसी न किसी जिला में ससुराल पड़ता है।

श्री हिन्द केशरी यादव : सभापति जी, माननीय श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा ने जो संकल्प लाया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सरकार-छोरशाखी सरकार है। इसके द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन आनेवाला नहीं है। यह जानते हुए भी आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मुंगेर को जिस ओर लोगों ने करीब से देखा

है उसी तरह से मैंने भी मुंगेर को करीब से देखने का प्रयास किया है। मुंगेर श्री बाबू की धरती रही है यही बहुत उपलब्धि है। जितनी श्रद्धा मुंगेर के लोगों को उनके लिये नहीं है उतनी श्रद्धा मुज्जफरपुर के माननीय सदस्य श्री रघुनाथ पांडेय को उनके प्रति है जिन्होंने सारी परम्परा को ताक पर रखकर मुज्जफरपुर में उनकी स्मृति में काम कर रहे हैं। मुंगेर के रहनेवाले चाहे मंत्री हों या कोई भी सदस्य हों उन्होंने नपुंशकता का परिचय दिया यही कारण है कि मुंगेर कमिशनरी नहीं बनाया जा सका। साथ-साथ मुंगेर जैसे जो भी पिछड़े इलाके हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि यदि उनको विकास के रास्ते पर लाना है तो उन्हें भी कमिशनरी बनाया जाय। पूर्वी चम्पाराण और बेतिया में डी० आई०जी० की पोस्टिंग हो गयी, क्रिमिनल को कंट्रोल करने के लिए यह तो दिया गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि महात्मा गाँधी के आन्दोलन की जो प्रथम धरती चम्पाराण और बेतिया रही है उसको भी कमीशनरी का दर्जा दिया जाय। महात्मा गाँधी जैसे महान पुरुष के आन्दोलन की प्रथम धरती को यदि आप कमिशनरी बनायेंगें तो आपके इतिहास में वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। सभापति महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुंगेर मेरा ससुराल पड़ता है, इसलिये इसको कमिशनरी बनाया जाय।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावनायें व्यक्त की है। उन सारी बातों से दूर हटकर एक बात की ओर आपके माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहता

हूँ। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज तक मुंगेर की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। आप जानते हैं कि श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुंगेर जिला के थे। उसके बाद आखिरी मुख्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह मुंगेर जिला के हीं रहे हैं। आप इस बात को देखिए कि हमारे मुंगेर के लोग अपनी ओर कम ध्यान देते हैं और बाद में जो लोग आए दूसरे जिला को काटकर अपने जिला को कमिशनरी बना लिए। इसलिए यह लाजिमी है कि मुंगेर को कमिशनरी बनाया जाय। मुंगेर की ऐतिहासिकता, भौगोलिक कारण और जन-मानस को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार पर दबाव देना चाहता हूँ कि मुंगेर को शोषण से बचाने के लिए अवश्य कमिशनरी बनाया जाय। मुंगेर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राजा रामचन्द्र जी शृंगी ऋषि के आश्रम में पानी पीए थे। इससे भी इसका ऐतिहासिक महत्व जुट जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, हमलोग अनुगृहित हैं माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा का कि उन्होंने गैर सरकारी संकल्प मुंगेर को कमिशनरी बनाने के लिए इस सदन में पेश किया है। मुंगेर की महत्ता के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मुंगेर में पैदा हुए देश के स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हुए। दूसरे नेताओं के बारे में भी चर्चा हुई। चाहे इस पक्ष में माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के सबों ने इस प्रस्ताव का

समर्थन किया है। किसी भी कोने से इसका विरोध नहीं है। सभी माननीय सदस्य इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं और सबों ने सरकार से आग्रह किया है कि इसको कमिशनरी बनाया जाय। मुख्यमंत्री इसको क्यों नहीं बनाये, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यहाँ यह कहना उचित होगा कि राजीव गांधी जी के समक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह ने घोषणा की थी कि इसको कमिशनरी बनाया जायगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार सदन में इसको स्वीकार नहीं करती है तो मैं काँग्रेस के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमलोग इस पर मत विभाजन की मांग करेंगे और उसमें आप लोग नैतिकता के आधार पर हमलोग इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें। हमलोग चाहते हैं कि मुंगेर कमिशनरी बने। सदन का भी पूरा समर्थन है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (बेलखंड) : सभापति महोदय, प्रशासनिक सुधार समिति की अनुशंसा के आलोक में छोटी-छोटी कमिशनरियाँ, छोटे-छोटे जिले और छोटे-छोटे सबडिविजन बनाए जाने लगे लेकिन अफसोस है कि उनके बनाने में जनहित का ख्याल, प्रशासन को दुरुस्त करने का ख्याल किए बिना प्रशासनिक इकाई का निर्माण होने लगा। सभापति महोदय, मुंगेर भौगोलिक दृष्टिकोण से, जनसंख्या की दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कमिशनरी के लिए डिजर्भ करता है लेकिन चूँकि वहाँ से विपक्ष के लोग जीतकर आये हैं, इसलिए मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

इस तरह से जब मुंगेर को कमिशनरी बनाने के लिए जनान्दोलन होता है तो सरकार प्रशासनिक सुधार समिति का गठन कर देती है। इन्होंने विक्रमगंज को अनुमंडल बनाया लेकिन जब हमलोग मुंगेर को कमिशनरी बनाने के लिए जनहित का सवाल उठाया तो इन्होंने इस मामले को प्रशासनिक सुधार समिति में भेज दिया है और प्रशासनिक सुधार समिति को तीन महीने में रिपोर्ट देना था लेकिन एक वर्ष बीत गया। इस समिति को अनुशंसा नहीं मिली। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय और प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय।

श्री दिनेश कुमार सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के गैर सरकारी संकल्प जो सदन के सामने है उसके पक्ष में कहा गया है कि मुंगेर को कमिशनरी का दर्जा दिया जाय। यह सही है कि इधर कुछ दिनों में बिहार में नये अनुमंडल, जिला और प्रमंडल का गठन किया गया है और वह इस परिस्थिति में हुआ है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी भी प्रमंडल, अनुमंडल, जिला या प्रखंड का गठन हुआ है वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जनसंख्या के आधार पर, औद्योगिक स्थिति के आधार पर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। पहले वर्ष में जब-जब सरकार आयी है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है और उनकी अनुशंसा के आधार पर काम हुआ है। आपको मालूम है और माननीय सदस्यों को भी

मालूम है कि सरकार ने 4 मई 1984 को प्रशासनिक ढांच में सुधार लाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिस समिति ने अपनी अनुशंसा 15 मार्च को दी है और सरकार इस पर विचार कर रही है और इसके बाद ही अन्य बात पर सरकार फैसला लेगी ।

सरकार जब भी किसी नए प्रमंडल या जिला का गठन करती है जैसा कि पहले बताया कि किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है । अभी आप देखेंगे कि माननीय सदस्य सर्वश्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, राजो सिंह और झाजी ने कहा कि मुंगेर को जनहित के ख्याल से, भौगोलिक स्थिति के ख्याल से प्रमंडल बनाया जाये लेकिन आप भूल गए कि खगड़िया गंगा के दूसरे किनारे पर है । खगड़िया को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोसी प्रमंडल में मिलाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और इस तरह की अनुशंसा उस कमिटी ने भी की है । गत सत्र में भी श्री वर्मा ने यह प्रश्न उठाया था और सरकार ने सदन को सूचित किया था कि इस वित्तीय वर्ष में, इस साल किसी भी नये प्रमंडल या जिला का गठन करने का विचार सरकार नहीं रखती है । यह सही है कि जैसा कि आवाज उठाया जाता है कि पुर्णिया को प्रमंडल बनाया जाय लेकिन माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर मुंगेर को प्रमंडल बना दिया जाय तो भागलपुर को एक ही जिला रह जायगा और शुरू से मुंगेर भागलपुर का अंग रहा है इसलिए तत्काल मुंगेर को अनुमंडल बनाने की घोषण करना संभव नहीं है । लेकिन माननीय सदस्यों की भावना को

देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी । इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा से अनुरोध करूँगा कि वे इसे वापस लें ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : मैं वापस नहीं लूँगा ।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरखू झा जी, क्या आप अपना अपेन्डमेन्ड वापस लेते हैं ?

श्री हरखू झा : मैं तहेदिल से वापस ले रहा हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि,-

माननीय सदस्य श्री हरखू झा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ।

(सदन की अनुमति हुई)

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

(विरोध पक्ष की ओर से आवाज कि इसको पुट कीजिए)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर भोटिंग कराइये ।

अध्यक्ष : आपका जो नियम है, उसके अनुसार गैर सरकारी संकल्प का समय 11 बजे तक था, वह समाप्त हुआ । आप इस पर मतदान के लिए समय का प्रस्ताव कीजिये, मैं उस पर भोट करा दूँगा ।

श्री रघुनाथ झा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के गैर सरकारी संकल्प पर मत लेने के लिए पांच मिनट का समय बढ़ाया जाय ।

डा० जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मतदान के लिए समय का प्रस्ताव कराने की परिपाटी नहीं करानी चाहिए । माननीय सदस्य चाहते हैं कि 5 मिनट बढ़ाकर मतदान करादिया जाय तो इस पर मतदान होना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संकल्प संख्या 2-गैर सरकारी प्रस्ताव पर विचार और मतदान के लिए सदन के निर्धारित समय से 5 मिनट बढ़ाया जाय ।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें । मैं समझता हूँ नां के पक्ष में बहुमत है ।

श्री रघुनाथ झा : हाँ के पक्ष में बहुमत है ।

(खड़े होकर मतदान क्रिया जारी)

(घंटी बजती रही)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य खड़े होकर इस प्रकार मतदान करेंगे । पहले हाँ के पक्ष में मत देनेवाले सदस्य खड़े हो जाएं ।

(इस अवसर पर “हाँ” पक्ष के माननीय सदस्यों की गिनती की गई)

अध्यक्ष : अब “ना” पक्ष में मत देनेवाले सदस्य खड़े हो जाएं ।

अध्यक्ष : खड़े होकर मतदान का पक्ष इस प्रकार है :-